स्पेसएक्स आईपीओ में निवेश करने निवेशकों ने कमाई का चोर रास्ता खोजा

उन कंपनियों में जमकर पैसा लगा रहे, जो स्पेसएक्स को करती हैं सामान सप्लाई

वाशिंगटन

एलन मस्क की कंपनी में पैसा लगाने के लिए दुनियाभर के निवेशक बेताब हैं, लेकिन एशिया के आम निवेशकों, जिनमें भारत, चीन और कोरिया शामिल हैं, उसके लिए इसमें सीधे निवेश का कोई रास्ता नहीं है।

ऐसे में मायूस होने के बजाय, निवेशकों ने कमाई का एक अनूठा और चोर रास्ता खोजा है, जिससे वे बिना सीधे शेयर खरीदे भी बंपर मुनाफा कमा सकते हैं। एशिया के निवेशकों ने भी ठीक ऐसा ही किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स में सीधे एंट्री न मिलने पर वे उन कंपनियों में जमकर पैसा लगा रहे हैं, जो स्पेसएक्स को सामान सप्लाई करती हैं या फिर व्यापक स्पेस सेक्टर से जुड़ी हैं। यही वो स्मार्ट फार्मूला है, जिससे स्पेसएक्स को होने वाले फायदे का लाभ उन सहायक कंपनियों को होगा, जो उसकी सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, और उन कंपनियों की कमाई से एशिया के निवेशक भी भरपूर पैसा बना पाएंगे।

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जापान और आस्ट्रेलिया को छोड़कर एशिया के किसी भी देश में रिटेल निवेशकों के पास इस आईपीओ का सीधा एक्सेस नहीं है। हालांकि, निवेशक तीन मुख्य तरीकों से इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। निवेशकों को पता है कि जब एलन मस्क का राकेट उड़ान भरेगा, तो उसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों की चांदी होगी। इसलिए लोग तेजी से स्पेस सप्लाई चेन वाली कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए, ताइवान की कंपनी डब्ल्यूएनसी कार्प के शेयर 175 फीसदी और यूनिवर्सल माइक्रोवेव टेक्नोलाजी के शेयर 147 फीसदी तक पहुंच गए हैं। इसी तरह, चीन की सनवे कम्युनिकेशन, जो स्टारलिंक के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, भी इस साल 60 फीसदी से ज्यादा उछल चुकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक लोग ऐसे फंड्स में पैसा लगा रहे हैं जो पहले से स्पेस टेक्नोलाजी में निवेश करते हैं। जैसे एआरके स्पेस एंड डिफेंस इनोवेशन ईटीएफ और टीमा स्पेस इनोवेटर्स ईटीएफ। इन फंड्स में पिछले कुछ समय में करोड़ों डालर का भारी निवेश आया है, क्योंकि इनके पास पहले से ही स्पेसएक्स की निजी इक्विटी के तौर पर हिस्सेदारी मौजूद है। तीसरा और सबसे सुरक्षित फार्मूला है नैस्डैक 100 इंडेक्स ट्रैकिंग फंड्स में पैसा लगाना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही स्पेसएक्स अमेरिकी बाजार में लिस्ट होगी, अपनी भारी-भरकम वैल्यू की वजह से यह बहुत जल्द नैस्डैक 100 इंडेक्स का हिस्सा बन सकती है। इसलिए लोग अभी से ही नैस्डैक से जुड़े फंड्स खरीदकर बैठ हैं, ताकि लिस्टिंग के बाद मिलने वाले लाभ का हिस्सा बन सकें।

न्यूज ब्रीफ

स्मार्टफोन की बिक्री में रिकार्ड 35 फीसदी तक की कमी, भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर मंडरा रहा मंदी का गहरा साया

नई दिल्ली। देश में स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों का असर अब बाजार पर साफ दिख रहा है। खुदरा विक्रेताओं के अनुसार मई में मोबाइल फोन की बिक्री में सालाना आधार पर रिकार्ड 30-35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह मेमोरी चिप की बढ़ती लागत है, जिसके चलते कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही हैं। यह गिरावट आनलाइन और आफलाइन दोनों बिक्री माध्यमों पर समान रूप से देखी जा रही है, जिससे भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर मंदी का गहरा साया मंडरा रहा है। स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों ने उपभोक्ताओं को खरीदारी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, जिससे मई महीने में बिक्री में भारी गिरावट आई है। काउंटरपाइंट रिसर्च के आंकड़ों से भी यह ट्रेंड पुष्ट होता है, जिसके मुताबिक मई में स्मार्टफोन शिपमेंट में 15-20 प्रतिशत की गिरावट आई। जून में भी इसी तरह की कमजोरी बने रहने की आशंका है। रिपोर्ट बताती है कि जनवरी से मई के बीच स्मार्टफोन की औसत कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि कुछ मामलों में कुल बढ़ोतरी 40-45 प्रतिशत तक पहुँच गई है। मेमोरी चिप की लागत में वृद्धि को इस कीमत बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस स्थिति से स्मार्टफोन उद्योग के लिए आने वाली तिमाही चुनौतियां भरी हो सकती है।

मई में इनोवा बनी सबसे ज्यादा बिक्री वाली कार

नई दिल्ली। टोयोटा ने भारतीय वाहन बाजार में मई 2026 के बिक्री आंकड़ों में मजबूत प्रदर्शन जारी रखा, और इस महीने टोयोटा इनोवा एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनकर उभरी। इनोवा और इसके उन्नत संस्करण की संयुक्त बिक्री 10 हजार से अधिक इकाइयों तक पहुंच गई, जो बड़े परिवारों और लंबी यात्राओं के लिए इस माडल की निरंतर लोकप्रियता को दर्शाती है। पिछले वर्ष की तुलना में इनोवा की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। बिक्री सूची में दूसरा स्थान टोयोटा हाइराइडर को मिला, जिसने भी दोहरे अंक की वार्षिक वृद्धि हासिल की। ईंधन दक्षता और आधुनिक सुविधाओं के कारण यह वाहन शहरी ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। हालांकि, कुछ माडलों ने कमजोर प्रदर्शन किया, जैसे ग्लैंजा की बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की बदलती पसंद का संकेत है। प्रीमियम श्रेणी में, फार्च्यूनर ने अपनी मजबूत साख और प्रदर्शन के कारण लोकप्रियता बनाए रखी, जिसकी बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी के अन्य माडलों में रुमियन ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जबकि टैसर की बिक्री में कुछ कमी आई। हील्क्स ने सीमित बाजार के बावजूद प्रभावशाली वृद्धि हासिल की।

मारुति सुजुकी ने पेश की प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम

नई दिल्ली। हाल ही में कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने जून माह से कुछ माडलों की कीमतों में वृद्धि का संकेत दिया था। 14 जून 2026 से पहले वाहन बुक कराने वाले ग्राहकों को बाद में होने वाली मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त भार नहीं उठाना पड़ेगा, इसके लिए कंपनी ने बेहतरीन योजना पेश की है। कंपनी ने प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम और सुहाना सफर नामक बचत आधारित वाहन ऋण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य छोटी कार खरीदने वाले ग्राहकों को बढ़ती कीमतों और वित्तीय दबाव से राहत दिलाना है। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बताया कि यह पहल पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों को आर्थिक बोझ के कारण अपनी योजना बदलने से रोकने के लिए की गई है। इस योजना का लाभ आल्टो के10, एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर जैसे लोकप्रिय एंट्री-लेवल माडलों पर मिलेगा। इसके साथ ही, सुहाना सफर योजना उन ग्राहकों के लिए मददगार है जिन्हें एकमुश्त अग्रिम राशि या मासिक किस्तों का प्रबंधन करने में कठिनाई होती है। इस स्कीम के तहत ग्राहक प्रत्येक माह एक निश्चित राशि (जो आमतौर पर कार की ईएमआई होती है) एक आरडी खाते में जमा कर सकते हैं। तीन से छह महीने तक नियमित बचत के बाद, जमा राशि का उपयोग वाहन खरीदते समय अग्रिम भुगतान के रूप में किया जा सकेगा।

एडवांस टैक्स की पहली किस्त 15 जून तक जमा करें, चूकने पर लगेगा ब्याज

आयकर विभाग ने करदाताओं को किया आगाह, 10,000 से अधिक अनुमानित देनदारी वालों के लिए अहम

नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। आयकर विभाग ने उन सभी करदाताओं को इस तारीख तक अपनी अनुमानित कर देनदारी का 15 प्रतिशत हिस्सा जमा करने की सलाह दी है, जिनकी वर्षभर की कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक बनती है। पे ऐज यू अर्न सिद्धांत पर आधारित यह व्यवस्था करदाताओं को ब्याज और जुर्माने से बचने में मदद करती है, जिससे पूरे वर्ष में किस्तों के माध्यम से टैक्स भुगतान की सुविधा मिलती है। आयकर नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की वित्त वर्ष के दौरान कुल अनुमानित टैक्स देनदारी, टीडीएस और टीसीएस को समायोजित करने के बाद, 10,000 रुपये से अधिक बनती है, तो उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है।

इसमें वेतनभोगी कर्मचारी (जिनकी अन्य स्रोतों से आय जैसे पूंजीगत लाभ होती है), फ्रीलांसर, सलाहकार, किराये से आय अर्जित करने वाले मकान मालिक, फिक्स्ड डिपाजिट से अधिक ब्याज कमाने वाले निवेशक तथा व्यावसायिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स चार चरणों में जमा किया जाना है: पहली किस्त 15 जून 2026 तक (कुल टैक्स का 15%), दूसरी 15 सितंबर 2026 तक (45 फीसदी), तीसरी 15 दिसंबर 2026 तक (75 फीसदी) और अंतिम किस्त 15 मार्च 2027 तक (100 फीसदी)। हालांकि, सभी करदाताओं पर यह नियम लागू नहीं होता।

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स से छूट प्राप्त है, बशर्ते उनकी कोई व्यवसायिक या पेशेवर आय न हो। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की आय व्यवसाय या प्रोफेशन से होती है, तो उन्हें भी अन्य करदाताओं की तरह एडवांस टैक्स जमा करना होगा। एडवांस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लाग इन कर ई-फाइल सेक्शन में ई-पे टैक्स विकल्प चुनना होगा, फिर वित्त वर्ष 2026-27 और एडवांस टैक्स (कोड 100) का चयन कर आवश्यक विवरण भरने के बाद भुगतान किया जा सकता है।

प्रिजम्पटिव टैक्सेशन योजना के तहत आने वाले छोटे कारोबारी या पेशेवर करदाताओं को हालांकि, पूरे वर्ष का 100 प्रतिशत एडवांस टैक्स एकमुश्त 15 मार्च 2027 तक जमा करना होता है। समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर करदाताओं को ब्याज के रूप में आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। यदि 31 मार्च तक कुल टैक्स देनदारी का कम से कम 90 प्रतिशत भुगतान नहीं किया जाता, तो आयकर अधिनियम की धारा 234बी के तहत बकाया राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाता है। इसी प्रकार, यदि निर्धारित तिमाही समय-सीमा के अनुसार एडवांस टैक्स जमा नहीं किया जाता, तो धारा 234सी के तहत भी 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूला जाता है।

बाजार की उठापटक में कमाई का मौका! तीन शेयरों में कमाई का मौका

नई दिल्ली

अगले एक साल में हो सकते हैं मालामाल

पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक कमाई के सुरक्षित और दमदार मौकों की तलाश में हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के प्रमुख ब्रोकरेज हाउसेस ने तीन ऐसे शेयरों की पहचान की है, जिनमें अगले एक साल के भीतर 61 फीसदी तक का शानदार रिटर्न मिल सकता है। इन कंपनियों के मजबूत बिजनेस माडल, बढ़ती सेक्टर मांग और भविष्य की विस्तार योजनाएं निवेशकों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकती हैं। चाइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने आरियनप्रो साल्यूशंस शेयर को खरीदने की सलाह दी है, जिसका लक्ष्य मूल्य 1,250 रुपए तय किया गया है। मौजूदा 775 रुपए के भाव से यह शेयर निवेशकों को 61 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित साफ्टवेयर, ट्रांजिट डिजिटाइजेशन और डेटा सेंटर जैसे भविष्य के सबसे बड़े ग्रोथ थीम्स पर काम कर रही है। वहीं एमके ग्लोबल ने अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा शेयर में निवेश की सलाह देते हुए 175 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। मौजूदा 121 रुपए के बाजार भाव से इसमें करीब 45 फीसदी की तेजी आ सकती है।

ब्रोकरेज के मुताबिक, मुंबई मेट्रोपालिटन रीजन पर केंद्रित इस रियल एस्टेट कंपनी ने कोविड के बाद शानदार वापसी की है, जिसकी प्री-सेल्स में 24 फीसदी की सीएजीआर दर्ज की गई है। आनंद राठी ने ल्यूमैक्स आटो टेक्नोलाजीज पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और अगले 12 महीनों के लिए 2,150 रुपए का लक्ष्य तय किया है। शेयर का मौजूदा भाव 1,634 रुपए है, जिससे इसमें लगभग 31 फीसदी का उछाल संभावित है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी पैसेंजर व्हीकल कंपोनेंट्स सेगमेंट में बेहद मजबूत स्थिति में है और इसके पास दमदार आर्डर बुक व प्रतिष्ठित ग्राहक हैं।

सरकार ने प्याज खरीद मूल्य बढ़ाकर 16.50 रुपए किलो किया

नई दिल्ली। सरकार ने प्याज किसानों को राहत देते हुए बफर स्टाक कार्यक्रम के तहत प्याज की खरीद दर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब यह 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम (1650 रुपए प्रति क्विंटल) की दर से खरीदी जाएगी, जो पहले 15.80 रुपए प्रति किलोग्राम थी। यह संशोधित मूल्य शनिवार से प्रभावी हो गया है, जो किसानों की आय सुनिश्चित करने और बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में सहायक होगा। यह कदम मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत बफर स्टाक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके माध्यम से सरकार बाजार में संतुलन बनाए रखती है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि मौजूदा मंडी कीमतों और भंडारण योग्य प्याज की गुणवत्ता के मद्देनजर यह फैसला हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि खरीद प्रक्रिया को बाजार की स्थितियों के हिसाब से बेहतर बनाने के लिए कीमत निर्धारण के तरीके में भी सुधार किया गया है।

ई100 ईंधन को हरी झंडी, भारत के ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरुआत

तेल आयात घटाने, पर्यावरण सुधारने और कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य

नई दिल्ली

भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 100 प्रतिशत एथेनाल (ई100) को वाहन ईंधन के रूप में कानूनी मंजूरी देने वाले नियमों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह फैसला देश की तेल आयात निर्भरता को कम करने, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और जैव ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ई100 को मिली कानूनी मान्यता, खुले नए अवसर केंद्र सरकार लंबे समय से एथेनाल आधारित ईंधन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अब 100 फीसदी एथेनाल को पूर्ण कानूनी मान्यता मिल गई है। इससे ई100 के व्यावसायिक उपयोग और इसके लिए आवश्यक मानकों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह कदम आटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी नए अवसर लेकर आया है, क्योंकि उन्हें अब ऐसे इंजन विकसित करने होंगे जो पूरी तरह एथेनाल पर चल सकें। कई कंपनियां फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले वाहनों के प्रोटोटाइप पहले ही पेश कर चुकी हैं और अब कानूनी स्पष्टता मिलने से इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन और बाजार में उतारना आसान हो जाएगा। किसानों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को लाभ इस नीति का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। गन्ना और मक्का जैसे कृषि उत्पादों का उपयोग एथेनाल उत्पादन में होने से किसानों को अपनी उपज का अतिरिक्त बाजार मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही, ई100 के बढ़ते उपयोग से भारत की भारी तेल आयात निर्भरता कम होगी, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचेगी। एथेनाल को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जिससे वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आने की उम्मीद है, जो पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा। बुनियादी ढांचे की तैयारी और भविष्य की राह हालांकि, इस बदलाव की राह में सबसे बड़ी चुनौती ई100 के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। पेट्रोल पंपों पर विशेष भंडारण और वितरण प्रणाली तैयार करनी होगी, जिसमें तकनीकी बदलावों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद, यह कदम भारत को पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करके स्वदेशी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर ले जाने का स्पष्ट संकेत देता है। यह योजना सफल होने पर न केवल किसानों और उद्योगों को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी भविष्य में अधिक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन का विकल्प उपलब्ध होगा।

एआई निवेश में नरमी के संकेत, वैश्विक बाजारों में इंफ्रास्ट्रक्चर से घटा रुझान

ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स से 10 अरब डालर की निकासी

मुंबई

दुनियाभर के बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) निवेश थीम की चमक अब थोड़ी फीकी पड़ती दिख रही है, खासकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई-चेन से जुड़ी कंपनियों में। ब्रोकरेज फर्म इलारा कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एआई आधारित निवेश के बड़े उछाल के बाद पहली बार निवेशक इन क्षेत्रों से अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं।

इसका सीधा असर ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट (जेएम) फंड्स पर पड़ा है, जिनसे बीते छह हफ्तों में रिकार्ड 10 अरब डालर की निकासी दर्ज की गई। इस वैश्विक बदलाव की आंच भारत पर भी पड़ रही है, जहां से विदेशी निवेशक लगातार पूंजी निकाल रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटी इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश को लेकर निवेशकों का उत्साह धीमा पड़ा है।

पिछले एक साल से अधिक समय में यह पहली बार है जब इस थीम की रफ्तार कमजोर पड़ी है। इस रुझान के चलते, उन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स से 10 अरब डालर की निकासी हुई है, जो ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों के जरिए एआई थीम में निवेश के लिए पसंदीदा बन गए थे। कमोडिटी इक्विटी और कीमती धातुओं वाले फंड्स से भी बड़ी मात्रा में पैसा बाहर निकला है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि एआई तकनीक से सीधे लाभ कमाने वाली प्रमुख कंपनियों में निवेशकों का भरोसा अब भी मजबूत बना हुआ है।

हालिया बाजार सुधार के दौरान अमेरिकी टेक-फोकस्ड फंड्स में रिकार्ड 9 अरब डालर का निवेश आया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में विदेशी निवेश लगातार 11वें सप्ताह भी सकारात्मक रहा और 10 अरब डालर के उच्च स्तर पर पहुंचा। यह दर्शाता है कि निवेशक अब अधिक चुनिंदा हो गए हैं और सीधे एआई से लाभान्वित होने वाली कोर कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

भारत के लिए यह ग्लोबल एआई निवेश थीम से जुड़ा बदलाव चुनौती भरा साबित हो रहा है। भारत और चीन उन प्रमुख बाजारों में शामिल हैं जहां से निवेशक पैसा निकालकर एआई से जुड़े वैश्विक अवसरों की ओर मोड़ रहे हैं। हालिया सप्ताह में भारत-केंद्रित फंड्स से लगभग 77 करोड़ डालर (770 मिलियन डालर) की निकासी हुई, जिसमें से 46 करोड़ डालर केवल फोकस्ड फंड्स से निकले। जेम फंड्स की तुलना में भारत का प्रदर्शन पिछले एक और तीन साल दोनों अवधियों में रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी मुख्य वजह वैश्विक पूंजी का द्व अवसरों की ओर शिफ्ट होना है।